International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 31-12-2022, Accepted: 17-01-2023, Published: 02-02-2023
Volume 9, Issue 1, 2023, Page No. 37-38

कोविड–19 महामारी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा पर इसका प्रभाव

संदीप कुमार
शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
शोध का मुख्य उदेश्य महामारी के संदर्भ में गरीबो के संकट को समझना है और उपयक्त नीति के साथ आगे बढ़ना है इस शोध में हम ये पड़ताल करेंगे की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर महामारी का क्या क्या प्रभाव पड़ा? पीडीएस महामारी के समय में गरीबों की समस्याओं को किस हद तक समाधान कर सका । हम यह समझने की कोशिश करेंगे की गरीबो को रहत प्रदान करने में पीडीएस का काम काज, रुकावट और अनसुलझी समस्याएँ क्या थी? वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने और यह विश्लेषण करने में उपयोगी होंगे कि क्या पीडीएस योजना सही लाभार्थियों तक पहुंची है और कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने में सफल रही है। हरियाणा में पीडीएस में सुधारों के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन के निष्कर्षों की अधिक प्रासंगिकता होगी। वर्तमान अध्ययन शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए एक ही विषय और अन्य संबंधित विषयों जैसे पीडीएस में 'एंड–टू–एंड कम्प्यूटरीकरण' के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की प्रभावशीलता पर उनके आगे के शोध में उपयोगी हो सकता है।

मूल शब्दः कोविड–19, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महामारी

शोध का मुख्य उदेश्य महामारी के संदर्भ में गरीबो के संकट को समझना है और उपयक्त नीति के साथ आगे बढ़ना है इस शोध में हम ये पड़ताल करेंगे की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर महामारी का क्या क्या प्रभाव पड़ा? पीडीएस महामारी के समय में गरीबों की भारत ने अत्यधिक संकटों के क्षण देखे हैंः प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा, भूकंप और भूस्खलन, सुरक्षा खतरे (बाहरी और आंतरिक दोनों), घातक बीमारियां, सांप्रदायिक दंगे आदि। हालाँकि, COVID-19 एक से अधिक तरीकों से अप्रत्याशित और अभूतपूर्व था। इसने न केवल संघीय सरकार को चौका दिया, बल्कि बीमारी की व्यापक सीमा और पूरी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव ने पर्यवेक्षकों के सबसे आशावादी लोगों को भी चौका दिया। महामारी ने भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सबसे कमजोर पक्ष को सामने लाया जो अब तक जीडीपी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय की बढ़ती संख्या की आड़ में छिपा हुआ था। महामारी के प्रसार के परिणामस्वरूप जो घटनाएँ सामने आईं, वे किसी तमाशे से कम नहीं थींः परिवहन में फंसे लाखों लोग, भोजन और आवश्यक वस्तुओं के लिए भागती हुई भीड़, कर्फ्यू, सैकड़ों मील पैदल चलकर घर वापस जाने वाले लाखों प्रवासी। महामारी के लिए भारत की पहली प्रतिक्रिया दुनिया के सबसे बड़े कोरोनावायरस लॉकडाउन के लागू होने के साथ आई, जब भारत के प्रधान मंत्री ने 24 मार्च 2020 को 1.3 बिलियन भारतीयों को घर में रहने का निर्देश दिया (सिंह एट अल।, 2020)। यह लॉकडाउन, शुरू में 21 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था, जिसके बाद कई विस्तार और सशर्त छूट दी गई, जिसका अर्थ था भारत के लगभग 90% कर्मचारियों की आजीविका का ठहराव जो अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अनुमान लगाया कि इन अनौपचारिक श्रमिकों में से 400 मिलियन को महामारी संकट (ILO, 2020) के दौरान गरीबी में गिरने का खतरा था।

हालांकि पूर्ण लॉकडाउन के माध्यम से महामारी के लिए भारत की पहली प्रतिक्रिया तेज थी, यह न केवल बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के बारे में था, बल्कि किसी भी सामाजिक सुरक्षा जाल से रहित बड़े अनौपचारिक कार्यबल के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में भी था। जब आय के स्रोत पूरी तरह से सूख चुके थे, तब पीडीएस तालाबंदी के दौरान भूख और अभाव के खिलाफ एक मजबूत कवच के रूप में उभरा। पीडीएस आसन्न खाद्य सुरक्षा संकटों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया के केंद्र में था क्योंकि सरकार की कई पहल पीडीएस को मजबूत करने पर केंद्रित थी। पीडीएस मौजूदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संचालित होता है

भारतीय आबादी के 67% को अत्यधिक रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य। एक पात्र व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न का हकदार है जिसमें गेहूं और चावल शामिल हैं, क्रमशः 2 और 3 की दर से। महामारी के कारण, भारत सरकार ने अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा की, जिससे प्रति व्यक्ति प्रति माह कुल खाद्य पात्रता 10 किलोग्राम हो गई (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2020)।

पीडीएस भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो मूल्य स्थिरता के उद्देश्यों को पूरा करता है और अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। एक प्रमुख योजना होने के नाते, पीडीएस से यह अपेक्षा की जाती है कि यह दक्षता के साथ और बिना किसी शिकायत के संचालित होगी। लेकिन कोविड महामारी के कारण इसका कामकाज प्रभावित हुआ और कोविड –19 संकट से बचने हेतु 2020 में भारत में किया गया राष्ट्रीय लॉकडाउन, दुनिया में सबसे कठोर लॉकडाउन में से एक था। लॉकडाउन के चलते लाखों लोग बेरोजगार हुए, और खाद्य आपूर्ति श्रंखलाओ में वयवधान और कोविद महामारी से उत्पन्न संकट ने लाखो लोगो को खाद्य असुरक्षित स्थितियों और ऋणग्रस्तता में ला दिया विश्व खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र समिति की खाद्य सुरक्षा और पोषण पर विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 83 से 132 मिलियन अतिरिक्त महामारी के कारण लोगों ने खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया। इसके अलावा, पोषण संबंधी सेवाओं सहित सार्वजनिक सेवाओं में गंभीर बाधाएं आईं– विशेष रूप से मध्याह्न भोजन को बंद कर दिया गया, क्योंकि अधिकांश राज्यों में 2020 के दौरान स्कूल और आंगनवाड़ी एक लम्बी अवधि के लिए बंद थे। 2020 में रोजगार और आय में भारी गिरावट के कारण खाद्य असुरक्षा में

वृद्धि हुई आईडीइनसाइट के न्यूनतम संकेतक दर्शाते हैं कि एक बड़ी संख्या में परिवार (26%) उन दिनों में सामान्य से कम मात्रा में भोजन कर रहे थे। एक बार फिर, राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद भी कठिनाई बनी रही। उदाहरण के लिए, सीएसई–एपीयू सर्वेक्षण में पाया गया कि अक्टूबर–दिसंबर 2020 में 60% परिवार लॉकडाउन के पूर्व की तुलना में कम खाना खा रहे थे द्य लॉकडाउन के दौरान, अप्रैल और मई में, 77% परिवार कम खाना खा रहे थे। वंचित समूहों के बीच स्थिति अनुमानित रूप से बदतर थी। उदाहरण के लिए, एक्शन एड की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10,000 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी) में से 35% मई 2020 के दौरान दिन में दो से कम समय का भोजन कर रहे थे। इसी तरह, बिहार में लगभग 20,000 लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से 60% के करीब जून 2020 में अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक दिन में दो वक्त का भोजन सुनिश्चित करने में असमर्थ थे और यही अनुपात जुलाई में भी रहा। सितंबर–अक्टूबर 2020 में, भोजन का अधिकार अभियान के "हंगर वॉच" सर्वेक्षण (भारत के सबसे गरीब घरों के वयस्क) में दो–तिहाई उत्तरदाताओं ने कहा कि वे उस समय लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम पौष्टिक भोजन खा रहे थे दृ जो भयावह है । नागुली और अंसारी के एक सर्वे में दिल्ली में रहने वाले अनेक लोगो ने यह स्वीकार किया की महामारी के दौरान उन्हें लम्बी कतारों और भीड़ का सामना करना पड़ता था भीड़ के बीच राशन लेना जोखिम भरा काम था। उत्तरदाताओं ने यह भी बताया की खाद्य वितरण में मात्रा और गुणवत्ता में असंगति थी, महामारी द्वारा लाए गए विनाश की निराशाजनक स्थिति निर्विवाद रूप से उपयुक्त नीतिगत समाधानों की मांग करती है।

निष्कर्ष

शोध का मुख्य उदेश्य महामारी के संदर्भ में गरीबो के संकट को समझना है और उपयक्त नीति के साथ आगे बढ़ना है इस शोध में हम ये पड़ताल करेंगे की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर महामारी का क्या क्या प्रभाव पड़ा? पीडीएस महामारी के समय में गरीबों की समस्याओं को किस हद तक समाधान कर सका । हम यह समझने की कोशिश करेंगे की गरीबो को रहत प्रदान करने में पीडीएस का काम काज, रुकावट और अनसुलझी समस्याएँ क्या थी? वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने और यह विश्लेषण करने में उपयोगी होंगे कि क्या पीडीएस योजना सही लाभार्थियों तक पहुंची है और कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने में सफल रही है। हरियाणा में पीडीएस में सुधारों के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन के निष्कर्षों की अधिक प्रासंगिकता होगी। वर्तमान अध्ययन शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए एक ही विषय और अन्य संबंधित विषयों जैसे पीडीएस में 'एंड–टू–एंड कम्प्यूटरीकरण' के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की प्रभावशीलता पर उनके आगे के शोध में उपयोगी हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. बलानी एस 2013 सामाजिक विभिन्नताएं सर्व नातमक रिपोर्ट पेपर आई डी 5628 ई सामाजिक विज्ञान
2. भाग्य श्री पी.जी पी.डी.एस सिस्टम पर कोलचछल निगम की रिपोर्ट (८) 3 6168
3. अग्रवाल के – कोरोना लॉकडाउन के दौरान भुखमरी और गरीबी आई एफ पी आर आई रिपोर्ट 2019–20
4. स्वाति नारायण पी डी एस सिस्टम की एक सकारात्मक पहल भारतीय मानवीय विकास लेख